सरकारी कोटे से रियायती दरों पर कितनी मात्रा में कागज आवंटित किया गया। उन समाचारपत्रों के नाम क्या है तथा वे किस-किस भाषा में प्रकाशित होते हैं ; और

(ख) उन समाचारपत्रों के नाम क्या हैं जिन्होंने आवंटित कोटे का पूरा-पूरा उपयोग कर लिया है ?

सूचना और प्रसारण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री आरिफ मोहम्मद खान) : (क) समाचारपत्रों को अखबारी कागज रियायती दरों पर नहीं दिया जाता। तथापि, आयातित अखबारी कागज पर सीमा शुल्क से छोटे समाचारपत्रों को पूर्ण राहत और मझोले समाचारपत्रों को दो-तिहाई राहत दी जाती है।

विभिन्न समाचारपत्रों को, अर्थात् बड़े समाचारपत्रों, मझोले समाचारपत्रों और लघु समाचारपत्रों की श्रेणियों में, 1977 से दिसम्बर, 1982 तक की अवधि के दौरान आवंटित कागज की कुल मात्रा इस प्रकार है :—

(टन)

1976–77	.	2,05,136
1977–78	.	2,41,992
1978–79	.	3,02,931
1979–80	.	3,42,900
1980–81	.	3,69,484
1981–82	.	3,53,672

(दिसम्बर, 1981 तक)

(ख) अधिकांश समाचारपत्र अखबारी कागज के आवंटित कोटे का पूरा उपयोग करते हैं। ऐसे मामलों में जहां अखबारी कागज के आवंटित कोटे का कम उपयोग हुआ ध्यान में आता है, शेष मात्रा को अगले वर्ष में ले लिया जाता है और उसको अनुवर्ती वर्ष के कोटे में समंजित कर दिया जाता है। 1977–78 से 1980–81 तक के वर्षों में जहां भी कम खपत हुई ध्यान में आई उसको अनुवर्ती वर्षों के कोटे में समंजित कर दिया गया। 1980–81 में आवंटित अखबारी कागज की खपत की जांच पड़ताल की जाएगी और यदि कोई कम खपत पाई गई तो उसे 1982–83 के दौरान अखबारी कागज के आवंटन के लिए आवेदनपत्रों को अन्तिम रूप देते समय समंजित कर दिया जाएगा।

Salary structure of employees in private companies

†2340-A. SHRI YOGENDRA SHARMA: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the October 1981 issue of the Reserve Bank of India bulletin wherein it is stated that the large public limited companies in the private sector have increased the emoluments of high salaried employees by 20.7 per cent while those of all employees rose by only 11.5 per cent; and

(b) if so, whether Government propose to take any steps to reduce the disparity in remuneration of these employees?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI JAGANNATH KAUSHAL): (a) Yes, Sir.

(b) The extant provision of the Companies Act, 1956 are concerned only with the regulation of the remuneration of the managerial personnel (Managing Directors and Wholetime

†Previously Unstarred Question 2389, transferred from the 23rd March, 1982.

Directors) of public limited companies and of such private limited companies as are subsidiaries of public limited companies. These form a very insignificant proportion of the total number of employees in the Corporate Sector. There is, at present no provision in the Companies Act to regulate the remuneration of other employees in the private sector. The question whether Companies Act should be amended to bring the remuneration payable to its other Senior Executives (other than Managaing Directors and Whole-time Directors etc.) also within the ambit of Companies Act, though income ceilings, is still under consideration of the Government.

कोयले का मूल्य

†2340-ख. **श्री कलराज मिश्र :** क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इनके मंत्रालय को कोयले के मूल्य में हुई वृद्धि की जानकारी है, जैसा कि कतिपय समाचारपत्रों में समाचार छपे हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि वित्त मंत्रालय ने उनके मंत्रालय के साथ बातचीत की है ; और

(ग) यदि हां, तो यह बातचीत कब हुई और इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया ?

ऊर्जा मंत्रालय के कोयला विभाग में राज्य मंत्री (श्री गंगी शंकर मिश्र) : (क) से (ग) कोयले के खान-मुहाना मूल्यों में अन्तिम संशोधन 14-2-1981 को किया गया था । उस दिन समितियों की लागतों में वृद्धि के कारण कोल इंडिया लि० ने कुछ प्रस्ताव रखे हैं । निर्णय का एलान यथा-समय किया जाएगा ।

†Previously Unstarred Question 2482, transferred from the 23rd March, 1982.

Memorandum from AINPCC employees Federation regarding collapse of Sewa Nagar fly-over bridge

†2340-C. SHRI DIPEN GHOSE: Will the Minister of ENERGY be pleased to state:

(a) whether Government have received a memorandum dated the 11th December, 1981 by the All India National Project Construction Corporation Ltd., Employees Federation regarding the collapse of Sewa Nagar Fly-over bridge in Delhi; and

(b) if so, what is Government's reaction thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF ENERGY (SHRI VIKRAM MAHAJAN): (a) Yes, Sir.

(b) The Sewanagar Flyover is being constructed by the National Projects Construction Corporation on behalf of the Railways. The Ministry of Railways has already ordered a high-powered enquiry committee to go into the cause of the collapse and recommend remedial measures to avoid such incidents in future.

---

12 NOON

RE. SPECIAL MENTIONS

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI (Maharashtra): On Friday you allowed me to make a special mention. You said you would wait for five minutes.

MR. CHAIRMAN: About?

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: About the NAFED and the NCCF. You said you will wait.

MR. CHAIRMAN: He will hear you.

SHRI ARVIND GANESH KULKARNI: But who will give the direction? You gave the directive here. Is Mr. Deputy Chairman competent. (*Interruptions*)

†Previously Unstarred Question 2641, transferred from the 25th March, 1982.